PRGI : APHIN/26/A3657

पेन पॉवर

हिंदी दैनिक समाचार पत्र

वर्ष - 1 अंक - 14 बुदवार, जुलाई 22, 2026 *विशाखापट्टनम* संपादकः गंट्यादा अप्पाराव पृष्ठों. 4 मूल्य. 1रु

संसद मार्च के समर्थन में प्रदर्शन

राहुल–प्रियंका हिरासत में

नयी दिल्ली (एजेंसी): स्वतंत्र भारत की राजनीति के सबसे नाटकीय दिनों में से एक मंगलवार को देखने को मिला, जब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रश्नपत्र लीक और छात्रों पर कथित ''हमले'' के विरोध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास तक कांग्रेस के मार्च का नेतृत्व किया। कई घंटे तक चले धरने के बाद पुलिस ने प्रदर्शन समाप्त कराते हुए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और अन्य नेताओं को हिरासत में ले लिया।

कॉकरोच जनता पार्टी (ब्भ्च्) के संसद मार्च के एक दिन बाद केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ाने के उद्देश्य से राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी वाड्रा मंगलवार दोपहर 10, राजाजी मार्ग स्थित कांग्रेस अध्यक्ष के आवास पर एकत्र हुए। वहां से वे प्रधानमंत्री आवास 7, लोक कल्याण मार्ग की ओर मार्च करते हुए पहुंचे।

घटनाक्रम के दौरान एक अभूतपूर्व स्थिति तब बनी जब प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह स्वयं प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे और राहुल गांधी से बातचीत की। हालांकि, बातचीत बेनतीजा रही और बाद में पुलिस ने धरना समाप्त करा दिया।

राहुल गांधी सड़क पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे थे और हटने से इनकार कर रहे थे। उन्हें हटाने के दौरान पुलिसकर्मियों ने घेर लिया और बाद में उन्हें जबरन वहां से ले जाया गया। इस दौरान उनकी नाक से खून निकलता भी दिखाई दिया। पुलिस कार्रवाई के बाद पत्रकारों से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा, ''भारत में लोकतंत्र अभी यहीं दिखाई दे रहा है।''

सूत्रों के अनुसार, राहुल गांधी ने रातभर धरना जारी रखने की योजना बनाई थी। उन्होंने लोगों से प्रधानमंत्री आवास के बाहर चल रहे प्रदर्शन में शामिल होने की अपील भी की थी।

उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, ''छात्रों पर हमला हर भारतीय परिवार पर हमला है। प्रधानमंत्री मोदी सोचते हैं कि वे बिना जवाब दिए और बिना किसी परिणाम के बच निकलेंगे। ऐसा नहीं होगा। मैं हर देशभक्त भारतीय से अपील करता हूं कि छात्रों को न्याय दिलाने के लिए प्रधानमंत्री आवास के सामने ध रने में शामिल हों।''

राहुल गांधी और जितेंद्र सिंह के बीच हुई बातचीत के बाद कांग्रेस नेताओं ने कहा कि वार्ता किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची। कांग्रेस सांसद सैयद नासिर हुसैन ने कहा,

'सरकार चाहती थी कि हम प्रदर्शन वापस ले लें, लेकिन हमारी मांगें पूरी नहीं हुईं। हम केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और पेपर लीक मुद्दे पर संसद में चर्चा चाहते हैं।''

वहीं, जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने पहले संसद में छम्म्ज और अन्य पेपर लीक मामलों पर चर्चा होने की स्थिति में प्रदर्शन समाप्त करने की बात कही थी, लेकिन बाद में उन्होंने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की नई मांग जोड़ दी।

मंगलवार शाम करीब 6:40 बजे पुलिस ने प्रदर्शन हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी।

इससे पहले सोमवार को कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च के दौरान पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स द्वारा लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया था। संगठन ने दावा किया था कि कई प्रदर्शनकारी घायल हुए और खून से लथपथ हो गए।

हालांकि, दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों ने उग्र और हिंसक व्यवहार किया, पुलिसकर्मियों पर पथराव किया, सरकारी वाहनों को नुकसान पहुंचाया और व्यापक हिंसा की। पुलिस के अनुसार, इस दौरान 118 पुलिसकर्मी, जिनमें वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे, घायल हुए।

मंगलवार के धरने की शुरुआत में राहुल गांधी ने कहा कि यह प्रदर्शन छात्रों के खिलाफ हुई कथित ''बर्बरता'' के लिए सरकार से जवाबदेही मांगने के उद्देश्य से किया जा रहा है। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ते हुए प्रध ानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की भी मांग की।

आंध्र प्रदेश को एक और अंतरराष्ट्रीय निवेश

यूएई स्थापित करेगा फूड क्लस्टर

अमरावती, 21 जुलाई: इस वर्ष दावोस शिखर सम्मेलन के दौरान हुए एक और महत्वपूर्ण समझौते के क्रियान्वयन की दिशा में बड़ा कदम बढ़ा है। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने आंध्र प्रदेश में एक फूड क्लस्टर स्थापित करने की पहल की है। मंगलवार को राज्य सचिवालय में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडु से यूएई के अर्थव्यवस्था एवं पर्यटन मंत्री अब्दुल्ला बिन तौक अल मरी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि ामंडल ने मुलाकात की। बैठक के दौरान आंध्र प्रदेश में फूड क्लस्टर की स्थापना को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। इस वर्ष दावोस यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडु द्वारा दिए गए आमंत्रण के जवाब में यूएई ने राज्य में फूड क्लस्टर स्थापित करने की अपनी तत्परता व्यक्त की। यूएई ने आंध्र प्रदेश के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में एक मजबूत वैल्यू चेन विकसित करने का निर्णय लिया है। इसी उद्देश्य से आंध्र प्रदेश सरकार और संयुक्त अरब अमीरात के बीच साझेदारी स्थापित की गई है। इस साझेदारी के तहत आम, केला, कोको तथा अन्य बागवानी

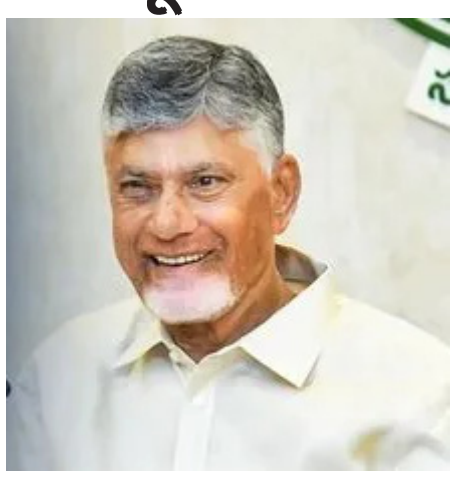

उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने के लिए एक व्यापक वैल्यू चेन विकसित की जाएगी। बैठक में यूएई प्रतिनिधिमंडल के अलावा मंत्री टी.जी. भरत, खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उद्योग विभाग तथा आंध्र प्रदेश आर्थिक विकास बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।

तम्मिनेनी सीताराम के कथित भूमि घोटालों पर कार्रवाई होगी: मंत्री अनगानी

(पेन पॉवर न्यूज):
अमरावती, 21 जुलाई: आंध्र प्रदेश के राजस्व मंत्री अनगानी सत्य प्रसाद ने स्पष्ट किया कि वाईएसआरसीपी नेता और आंध्र प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष तम्मिनेनी सीताराम से जुड़े कथित भूमि अनियमितताओं के मामलों में निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि गोवा के राज्यपाल अशोक गजपति राजू की भूमि से जुड़े मामलों में कथित रूप से अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मंत्री ने चेतावनी दी कि पूर्व मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी के पांच वर्षीय शासनकाल के दौरान हुई सभी कथित अनियमितताओं की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मंगलवार को अमरावती में मीडिया से बातचीत करते हुए अनगानी ने वाईएसआरसीपी पर निशाना साधा और उसे "कुल्हाड़ी पार्टी" बताते हुए आरोप लगाया कि वह राजनीतिक स्वार्थ के लिए झूठे आरोप लगा रही है। मंत्री ने कहा कि रजिस्ट्रेशन सर्विस केंद्र का उद्देश्य पंजीकरण कार्यालयों में आम लोगों को होने वाली परेशानियों को दूर करना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इन केंद्रों से जनता को लाभ होगा और किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अनगानी ने बताया कि दस्तावेज लेखकों (डॉक्यूमेंट राइटर्स) से इस विषय पर चर्चा की गई थी और उन्होंने भी इस पहल पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे कुछ व्यक्तियों और राजनीतिक दलों द्वारा अपने स्वार्थ के लिए बिछाए जा रहे जाल में न फंसें। मंत्री ने कहा कि आरएसके प्रणाली राजस्व प्रशासन में सुध ार के तहत शुरू की जा रही एक नई तकनीकी पहल है, जो राज्य में राजस्व सेवाओं को अधिक पारदर्शी और जनहितकारी बनाएगी।

पेनुकोंडा की पेयजल समस्या के समाधान की दिशा में एक और बड़ा कदम

अमरावती, 21 जुलाई: आंध्र प्रदेश सरकार ने श्री सत्य साई जिले की पेनुकोंडा नगर पंचायत के लोगों की पेयजल समस्या के समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। पेनुकोंडा नगर को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए गोल्लापल्ली जलाशय से 0.18 टीएमसी पानी आवंटित करते हुए सरकार ने आदेश (जीओ) जारी किया है। यह पानी हंद्री–नीवा सुजला स्रवंति परियोजना से उपलब्ध कराया जाएगा। इस संबंध में जल संसाधन विभाग ने जी.ओ. आर.टी. संख्या 395 जारी की है। सरकारी आदेश के अनुसार, पेनुकोंडा नगर पंचायत की पेयजल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 0.18 टीएमसी पानी आवंटित किया गया है। इस पानी का उपयोग अमृत 2.0 योजना के तहत पेयजल अवसंरचना विकसित करने के लिए किया जाएगा। सरकार ने कहा कि यह निर्णय राज्य की जल नीति के अनुरूप लिया गया है, जिसमें पेयजल आवश्यकताओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। इंजीनियर–इन–चीफ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सरकार ने जल आवंटन से संबंधित आगे की कार्रवाई करने के लिए इंजीनियर–इन–चीफ को निर्देश दिए हैं। अधिकारियों का मानना है कि इस निर्णय से पेनुकोंडा के लोगों की लंबे समय से चली आ रही पेयजल समस्या के समाधान की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ा है।

अपराध नियंत्रण के लिए विशेष टास्क फोर्स का गठन होगा: गृह मंत्री अनिता

(पेन पॉवर न्यूज):
अमरावती, 21 जुलाई: आंध्र प्रदेश की गृह मंत्री वंगलापुडी अनिता ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। हालांकि, उन्होंने जोर देकर कहा कि इस स्वतंत्रता का उपयोग जिम्मेदारी के साथ किया जाना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि सोशल मीडिया पर झूठा प्रचार करने और आपत्तिजनक टिप्पणियां करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

मंगलवार को आंध्र प्रदेश पुलिस विभाग द्वारा आयोजित "फ्यूचर रेडी एपी पुलिस रिट्रीट दृ टू डेज वर्कशॉप" में भाग लेते हुए गृह मंत्री ने यह बात कही।

"हमने ईगल विशेष प्रणाली शुरू की है"

अनिता ने बताया कि यह कार्यशाला दो दिनों तक चलेगी और इसके समापन कार्यक्रम में बुधवार को मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडु शामिल होंगे। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे अपने सुझाव और सिफारिशें मुख्यमंत्री के साथ साझा करें। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग के तहत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और अलग–अलग विभागों को एक मंच पर लाया गया है। उनके अनुसार, यह "फ्यूचर रेडी" रिट्रीट पुलिस व्यवस्था को और सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

गृह मंत्री ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों और हमलों पर सरकार ने कार्रवाई की है। उन्होंने यह भी बताया कि गांजा की समस्या पर नियंत्रण के लिए ईगल (म्।ळस्) विशेष प्रणाली शुरू की गई है।

"हमने गांजा की खेती पर रोक लगाई है"

अनिता ने कहा कि पुलिस के सहयोग से राज्य में गांजा की खेती पर काफी हद तक नियंत्रण पाया गया है। उन्होंने एन. चंद्रबाबू नायडु को एक अत्यंत अनुभवी नेता बताते हुए कहा कि वर्ष 2028 तक वे अपने राजनीतिक जीवन के 50 वर्ष पूरे कर लेंगे।

उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडु बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी की बात ध्यान से सुनते हैं। अपने 50 वर्षों के राजनीतिक अनुभव में उन्होंने अनेक पुलिस अधिकारियों के साथ काम किया है और व्यापक प्रशासनिक अनुभव अर्जित किया है। गृह मंत्री ने साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण की आवश्यकता पर बल दिया और बताया कि राज्य

में अपराध नियंत्रण को और मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री जल्द ही एक विशेष टास्क फोर्स का गठन करने जा रहे हैं।

भूमि कब्जे का सूत्रधार सीताराम, उसका क्रियान्वयन करने वाला उसका बेटा: विधायक कूना रविकुमार

(पेन पॉवर न्यूज):
श्रीकाकुलम, 21 जुलाई: टीडीपी विधायक कूना रविकुमार ने वाईएसआरसीपी नेताओं पर तीखा हमला बोला। मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वाईएसआरसीपी "गोड्डली (कुल्हाड़ी) पार्टी" है और उसके अध्यक्ष वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि वाईएसआरसीपी शासनकाल में पार्टी अध्यक्ष से लेकर निचले स्तर के नेताओं तक सभी ने अवैध गतिविधियां और अत्याचार किए।

उन्होंने वाईएसआरसीपी को भारत की सबसे अराजक राजनीतिक पार्टियों में से एक बताया और कहा कि 2019 से 2024 के बीच राज्य में गुटबाजी आधारित शासन चला। उनके अनुसार, वाईएसआरसीपी सरकार के दौरान भूमि कब्जे और सत्ता के दुरुपयोग की घटनाएं बड़े पैमाने पर हुईं। उन्होंने आरोप लगाया कि छह बार विधायक और विधानसभा अध्यक्ष रह चुके तम्मिनेनी सीताराम ने एक जीवित व्यक्ति को कागजों में मृत दिखाकर उसकी संपत्ति हड़पने की साजिश रची।

विधायक ने यह भी आरोप लगाया कि तम्मिनेनी सीताराम ने विधानसभा में तत्कालीन विपक्ष के नेता का अपमान किया था। उन्होंने कहा कि उन्होंने उसी समय कह दिया था कि सीताराम स्पीकर पद के योग्य नहीं हैं। रविकुमार ने वाईएसआरसीपी को "चोरों की पार्टी" बताते हुए सवाल किया कि वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी तम्मिनेनी पर लगे आरोपों पर चुप क्यों हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि एक आम आदमी की जमीन को फर्जी दस्तावेजों के जरिए हड़पने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि भूमि कब्जे के मामले में तम्मिनेनी सीताराम सूत्रधार हैं, जबकि उनके बेटे ने उसे अंजाम दिया। पूर्व मंत्री सीदिरी अप्पलराजू का जिक्र करते हुए रविकुमार ने कहा कि उनके आचरण को पूरा राज्य देख चुका है। उन्होंने आरोप लगाया

कि जब अप्पलराजू के बेटे ने कथित रूप से मोटरसाइकिल से टक्कर मारकर एक व्यक्ति की जान ले ली, तब उसकी जगह किसी अन्य व्यक्ति को खड़ा कर साक्ष्यों में हेरफेर की गई। उन्होंने कहा कि जगन द्वारा आरोपी को केवल 18 साल का लड़का बताना शर्मनाक है। रविकुमार ने आगे वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उनके अपने चाचा की हत्या के मामले में भी साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने का इतिहास रहा है। उन्होंने सवाल किया कि जो लोग साक्ष्यों में हेरफेर कर कानून को गुमराह करते हैं, क्या वे राजनीति के योग्य हैं? उन्होंने आरोप लगाया कि सीदिरी अप्पलराजू ने एक निर्दोष व्यक्ति को दोषी साबित करने की कोशिश की। यह कहते हुए कि कानून किसी एक व्यक्ति का नहीं होता, रविकुमार ने पुलिस से वाईएसआरसीपी नेताओं की कथित अवैध गतिविधियों पर ध्यान देने की अपील की।

पिछली सरकार के दौरान सवालों के घेरे में आए पोलावरम प्रोजेक्ट को हमने फिर से बचाया: मंत्री निम्मला रामानायडु

(पेन पॉवर न्यूज):
अमरावती, 21 जुलाई: आंध्र प्रदेश के जल संसाधन मंत्री निम्मला रामानायडु ने कहा कि पानी के महत्व को एन.टी. रामाराव (एनटीआर) से लेकर एन. चंद्रबाबू नायडु तक सभी ने पहचाना है। मंगलवार को मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने दो वर्षों की सरकारी उपलब्धियों तथा पोलावरम एवं अन्य सिंचाई परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा की और वाईएसआरसीपी सरकार की आलोचना की।

उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार को एक ओर वेंटिलेटर पर चल रही अर्थव्यवस्था और दूसरी ओर पूरी तरह से बर्बाद सिंचाई व्यवस्था विरासत में मिली। उन्होंने कहा कि आज सिंचाई विभाग ने एक सुव्यवस्थित कार्य–योजना (कैलेंडर) तैयार कर ली है। पोलावरम परियोजना को राज्य के लिए वरदान और जीवनरेखा बताते हुए उन्होंने कहा कि टीडीपी सरकार के कार्यकाल में ही परियोजना का 72 प्रतिशत काम पूरा हो चुका था। यदि टीडीपी सरकार सत्ता में बनी रहती, तो यह परियोजना 2021–22 तक पूरी हो जाती। मंत्री ने 2019 में सत्ता में आई सरकार की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि उसने 17 महीनों तक पोलावरम परियोजना की पूरी तरह उपेक्षा की। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार पोलावरम विस्थापितों से किया गया एक भी वादा पूरा नहीं कर सकी। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार द्वारा पोलावरम के लिए जारी किए गए धन को भी दूसरी जगह मोड़ दिया गया। उनके अनुसार, परियोजना से संबंधित प्रतिपूर्ति (रीइम्बर्समेंट) राशि का भी दुरुपयोग किया गया। रामानायडु ने कहा कि ईसीआरएफ डैम पोलावरम परियोजना का अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसके निर्माण का 31 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। उन्होंने बताया कि परियोजना की दाईं और बाईं ओर की कनेक्टिविटी को पूरा करने के लिए दिन–रात काम किया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि पिछले दो वर्षोंमेंही पोलावरम विस्थापित परिवारों

को 2,250 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। उन्होंने दावा किया कि वाईएसआरसीपी के पांच वर्षोंके शासनकाल में सवालों के घेरे में आ चुकी इस परियोजना को वर्तमान सरकार ने फिर से सुरक्षित किया और आगे बढ़ाया है।

संपादकीय

'कॉकरोचों' ने तोड़ी सत्ता की गहरी नींद

कॉकरोच जनता पार्टी ने दिल्ली की सत्ता को झकझोर दिया है। पुलिस बैरिकेड, लाठीचार्ज और आंसू गैस के बावजूद प्रदर्शनकारी बिना डरे संसद भवन की ओर बढ़ते रहे। संसद मार्ग युद्धभूमि जैसा दिखाई दिया और पूरी दिल्ली में तनाव का माहौल बन गया। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने पाँच स्टेशन बंद कर दिए, जबकि इंटरनेट सेवाएँ भी निलंबित कर दी गईं। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन जंतर–मंतर से निकाली गई "चलो संसद" रैली में कॉकरोच जनता पार्टी ने नीट–यूजी पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग की। यह रैली बाढ़ की तरह आगे बढ़ी, जिसे सुरक्षा बल रोक नहीं पाए। इससे केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ गया। एक ओर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान संसद भवन के भीतर बैठक कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने आंदोलन का नेतृत्व कर रहे नेताओं से बातचीत की। प्रदर्शनकारियों ने जेपी नड्डा को तीन प्रमुख मांगें सौंपींकृपर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को तुरंत अस्पताल से रिहा किया जाए, पेपर लीक की जिम्मेदारी तय करते हुए धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाया जाए, और परीक्षा संबंधी अव्यवस्थाओं के कारण आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को एक–एक करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगें पूरी नहीं हुईं तो आंदोलन जारी रहेगा। सीजेपी प्रतिनिधियों के अनुसार जेपी नड्डा ने केंद्र सरकार से इस विषय पर चर्चा करने का आश्वासन दिया। इस बीच जंतर–मंतर पर तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने अपना अनशन समाप्त कर दिया, जबकि 23 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे आइसा के छात्र नेताओं ने भी अपना अनशन समाप्त कर दिया। हालांकि संगठन ने घोषणा की कि उसका संघर्ष जारी रहेगा। सोनम वांगचुक ने भी कुछ शर्तों के साथ अपना अनशन समाप्त करने की इच्छा जताई और अस्पताल से एक पत्र जारी किया। इस आंदोलन को विपक्षी दलों का व्यापक समर्थन मिला। राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की कड़ी निंदा की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर युवाओं के प्रति विरोधी रवैया अपनाने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने दावा किया कि मोदी सरकार के कार्यकाल में 152 परीक्षा पत्र लीक हुए, जिससे 7.5 करोड़ लोग प्रभावित हुए। केरल के सांसदों ने भी आंदोलन का समर्थन किया। हजारों छात्र सड़कों पर उतरकर इस आंदोलन के साथ खड़े हुए, जिससे केंद्र सरकार पर दबाव और बढ़ गया।

लेख के अनुसार, केंद्र सरकार ने शुरू से ही कॉकरोच जनता पार्टी को हल्के में लिया। पार्टी बनने के केवल दो दिनों के भीतर सोशल मीडिया पर उसके दो करोड़ समर्थक होने के बावजूद उसे गंभीरता से नहीं लिया गया। समर्थकों को "वायरस", "टुकड़े–टुकड़े गैंग" कहकर संबोधित किया गया और उन पर विदेशी ताकतों के समर्थन के आरोप लगाए गए। आंदोलन को कमजोर करने के लिए विभिन्न प्रयास किए गए। इसी प्रकार पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के अनशन को भी लंबे समय तक नजरअंदाज किया गया। बताया गया कि उनका वजन 10 किलोग्राम कम हो गया और स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देश पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वामपंथी दलों, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी तथा आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस अनशन को समर्थन दिया। कई नेता जंतर–मंतर पहुँचकर उनसे मिले और उनका हौसला बढ़ाया। लेख के अनुसार, यह केवल सरकार का हठ नहीं बल्कि आंदोलन को दबाने का प्रयास भी था। नीट पेपर लीक मामले से उपजे देशव्यापी आक्रोश के बीच कॉकरोच जनता पार्टी का उदय हुआ। भारत के जेन–जेड युवाओं ने बेरोजगारी, पेपर लीक और संस्थागत भ्रष्टाचार के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी तथा नेशनल पैरासिटिक फ्रंट जैसे डिजिटल मंच बनाए। ये ऑनलाइन अभियान युवाओं के असंतोष की सामूहिक अभिव्यक्ति बन गए। पार्टी के गठन के मात्र 48 घंटे के भीतर उसके एक्स (पूर्व ट्विटर) खाते पर लगभग 60 लाख फॉलोअर जुड़ गए। पेपर लीक के अलावा पार्टी की अन्य प्रमुख मांगों में सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीशों को सरकारी पद न दिए जाने, दलबदल विरोधी कानून को सख्ती से लागू करने, विधानमंडलों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने तथा कथित अवैध मीडिया संस्थानों के लाइसेंस रद्द करने की मांग शामिल है। लेख का निष्कर्ष है कि ये मांगें मोदी सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण हैं और भविष्य में कॉकरोच जनता पार्टी अपनी बढ़ती ताकत का किस प्रकार उपयोग करती है, यह देखने वाली बात होगी।

कारसेवा का शंखनाद : क्या मथुरा बनेगा निर्णायक मोर्चा?

सुरेश गांधी

अयोध्या का अध्याय अपने निर्णायक पड़ाव पर पहुंच चुका है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया केंद्र उभरता दिखाई दे रहा है—श्रीकृष्ण जन्मभूमि। वर्षों से अदालत की चौखट पर चल रहा यह विवाद अब केवल कानूनी बहस तक सीमित नहीं रह गया है। संत समाज की सक्रियता, अखाड़ा परिषद द्वारा 9 अगस्त को कारसेवा के आह्वान और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लगातार मुखर होते राजनीतिक तेवरों ने मथुरा को एक बार फिर राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में ला खड़ा किया है।

बीते दो दिनों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सार्वजनिक संबोधनों में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर सीधा राजनीतिक हमला बोलते हुए कहा कि यदि वे स्वयं को भगवान श्रीकृष्ण का वंशज बताते हैं, तो उन्हें श्रीकृष्ण जन्मभूमि के प्रश्न पर भी स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए। योगी ने इसे वोट बैंक की राजनीति से जोड़ते हुए विपक्ष पर तुष्टिकरण का आरोप लगाया। इन बयानों ने यह संकेत अवश्य दिया है कि मथुरा का मुद्दा अब केवल धार्मिक विमर्श नहीं, बल्कि वैचारिक और राजनीतिक बहस का भी केंद्र बन रहा है।यहीं से उत्तर प्रदेश की राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी दिखाई देती है। 2027 के विधानसभा चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन राजनीतिक दलों की रणनीतियां आकार लेने लगी हैं। भाजपा विकास, कानून-व्यवस्था और कल्याणकारी योजनाओं के साथ अपनी वैचारिक राजनीति को भी समानांतर गति देती रही है। ऐसे में श्रीकृष्ण जन्मभूमि का प्रश्न उसके व्यापक राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बन सकता है। हालांकि अभी तक इसे चुनावी एजेंडे के रूप में आधिकारिक

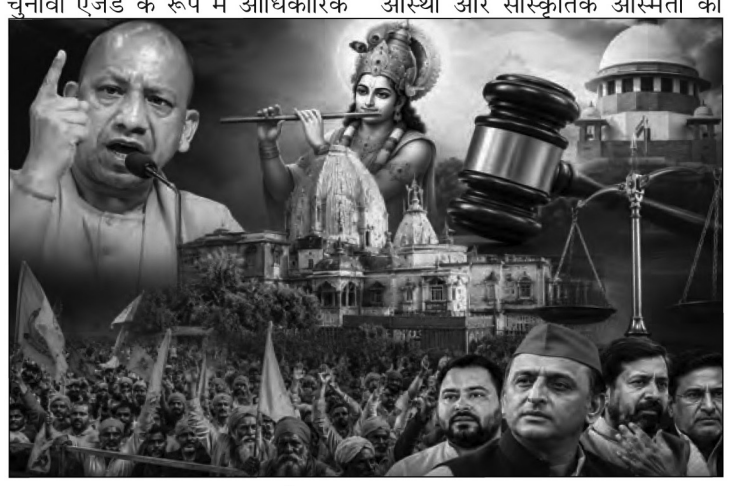

रूप से घोषित नहीं किया गया है।

इसलिए तथ्य यही कहते हैं कि यह मुद्दा 2027 की राजनीति को प्रभावित करने की क्षमता रखता है, लेकिन उसके स्वरूप का अंतिम निर्धारण आने वाले घटनाक्रम करेंगे।दूसरी ओर विपक्ष के सामने भी चुनौती कम नहीं है। समाजवादी पार्टी की राजनीति एक ओर अपने परंपरागत मुस्लिम समर्थन आधार पर टिकी है, वहीं यादव समाज की सांस्कृतिक पहचान भगवान श्रीकृष्ण से भी जुड़ी मानी जाती है। ऐसे में मथुरा का प्रश्न अखिलेश यादव के लिए केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि प्रतीकात्मक चुनौती भी बनता दिखाई देता है। संत समाज लगातार उनसे इस विषय पर स्पष्ट रुख की अपेक्षा जता रहा है।अखाड़ा परिषद का संदेश भी स्पष्ट है। संत समाज इसे सदियों पुरानी आस्था और सांस्कृतिक अस्मिता का अधूरा अध्याय मानते हुए आगे बढ़ाने की बात कर रहा है। वहीं विपक्ष इसे चुनावी ध्रुवीकरण की रणनीति के रूप में देख रहा है। यही भारतीय लोकतंत्र की जटिलता भी है-जहां एक ही विषय किसी के लिए आस्था का प्रश्न होता है, तो किसी के लिए राजनीति का। इस पूरे विवाद का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि से जुड़े अनेक मुकदमे अभी न्यायालय में विचाराधीन हैं। विवादित लगभग 13.37 एकड़ परिसर पर अंतिम निर्णय न्यायपालिका को ही करना है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्थायी समाधान भी वही होगा, जो संविधान और न्यायिक प्रक्रिया के अनुरूप निकले। मुख्यमंत्री योगी स्वयं भी अनेक अवसरों पर न्यायिक प्रक्रिया के सम्मान की बात दोहरा चुके हैं।

फिर भी राजनीति केवल अदालत के फैसलों की प्रतीक्षा नहीं करती; वह जनभावनाओं की दिशा भी पढ़ती है। इतिहास गवाह है कि अयोध्या का आंदोलन केवल न्यायालय के भीतर नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक विमर्श के समानांतर भी आगे बढ़ा था। यही कारण है कि अब यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठने लगा है कि क्या मथुरा भी उसी तरह व्यापक जनचर्चा का केंद्र बनेगी, या यह केवल वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों का अस्थायी उभार है।

इतिहास, आस्था और राजनीति-तीनों की अपनी-अपनी गति होती है। मथुरा भारतीय सभ्यता की स्मृति है, करोड़ों लोगों की श्रद्धा का केंद्र है और साथ ही एक संवेदनशील न्यायिक विषय भी। ऐसे में किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले यह स्वीकार करना होगा कि लोकतंत्र में आस्था और संविधान दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। आने वाले महीनों में यह स्पष्ट होगा कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि का प्रश्न न्यायालय की सीमाओं में ही रहेगा या उत्तर प्रदेश की राजनीति के सबसे प्रभावशाली विमर्श के रूप में स्थापित होगा। फिलहाल इतना तय है कि मथुरा ने दस्तक दे दी है। अब निगाहें इस पर हैं कि यह दस्तक इतिहास का नया अध्याय लिखेगी या केवल राजनीति के वर्तमान अध्याय का सबसे मुखर प्रतीक बनकर रह जाएगी।

श्रीकृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति अब टाली नहीं जा सकती अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुद्दे पर अपने रुख को और स्पष्ट करते हुए 9 अगस्त को कारसेवा का आह्वान किया है। परिषद के अध्यक्ष महंत रवींद्र पुरी ने कहा कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि करोड़ों सनातन श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है और इस विषय का समाधान शीघ्र होना चाहिए। उन्होंने कहा कि संत समाज लंबे समय से न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करता आया है, लेकिन आस्था के इस प्रश्न पर जनजागरण भी आवश्यक है।

श्रीकृष्ण जन्मभूमि केवल भूमि का प्रश्न नहीं, करोड़ों हिंदुओं की आस्था का विषय है। संत समाज संविधान और न्यायालय का सम्मान करता है, लेकिन समाज को जागृत करना भी हमारा दायित्व है। परिषद की ओर से कहा गया है कि प्रस्तावित कारसेवा का उद्देश्य श्रद्धालुओं को संगठित करना और श्रीकृष्ण जन्मभूमि से जुड़े विषय पर जनजागरण करना है। हालांकि इस पूरे विवाद से जुड़े विभिन्न मुकदमे अभी न्यायालय में लंबित हैं और अंतिम निर्णय न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही होगा।

जब कॉकरोच सेना ने इतिहास को झकझोर दिया...

महात्मा गांधी ने कहा था, '"इतिहास की दिशा बदलने के लिए हमेशा बड़ी शक्तियों की आवश्यकता नहीं होती। अपने लक्ष्य पर अटूट विश्वास रखने वाले कुछ दृढ़ निश्चयी लोग भी परिवर्तन ला सकते हैं।"' आज भारत जिस दौर से गुजर रहा है, उसे देखते हुए यह कथन बेहद प्रासंगिक लगता है।

नीट प्रश्नपत्र लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर पिछले एक महीने से आंदोलन कर रहे कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के कार्यकर्ताओं द्वारा सोमवार को संसद के मानसून सत्र के पहले दिन संसद घेराव का प्रयास हाल के समय की एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना बन गया। चार स्तर की बैरिकेडिंग, रैपिड एक्शन फोर्स, सीआरपीएफ, दिल्ली और त्रिपुरा पुलिस की भारी तैनाती, कई मेट्रो स्टेशनों की बंदी और इंटरनेट प्रतिबंध के बावजूद हजारों प्रदर्शनकारी संसद के द्वार तक पहुंच गए। पुलिस की लाठीचार्ज और बल प्रयोग के बावजूद युवाओं ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में घायल पड़े युवा उस दिन की घटनाओं के प्रत्यक्ष गवाह हैं।

एक दशक से अधिक समय तक विपक्ष के तमाम हमलों और आलोचनाओं से अप्रभावित दिखने वाली मोदी सरकार इस आंदोलन के बाद रक्षात्मक मुद्रा में दिखाई दे रही है। भाजपा के एक सांसद ने स्वीकार किया कि आंदोलन में कितने लोग शामिल हुए, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है, जितना उसका प्रभाव। जंतर–मंतर पर धरने में शामिल एक युवक ने कहा, "मेरे पिता भाजपा के बड़े नेता हैं, लेकिन जो कुछ हो रहा है, वह स्वस्थ लोकतांत्रिक संकेत नहीं है।" वहीं एक छात्र का कहना था, "जहां राजनीतिक दल विफल हो जाते हैं, वहां बच्चे और युवा सवाल पूछना शुरू कर देते हैं।"

दरअसल, कॉकरोच जनता पार्टी कोई पारंपरिक संगठन नहीं है। यह देश के वर्तमान दौर में दिशाहीन और निराश युवाओं की एक सामूहिक अभिव्यक्ति है। जंतर–मंतर पहुंचे लोग किसी राजनीतिक दल द्वारा जुटाए गए कार्यकर्ता नहीं थे। उनके लिए न बसों की व्यवस्था की गई थी, न ट्रेनों की। सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं ने ही उन्हें दिल्ली पहुंचने के लिए प्रेरित किया।

वे केवल नीट पेपर लीक से आक्रोशित होकर नहीं आए थे। बेरोजगारी, कम वेतन, व्यवस्था की खामियां और राजनीतिक दलों की चालबाजियों से परेशान युवा वहां एकत्र हुए थे। 14 से 28 वर्ष आयु वर्ग के इन युवाओं को वामपंथ और दक्षिणपंथ जैसी वैचारिक श्रेणियों में आसानी से नहीं बांधा जा सकता। उन्होंने आपातकाल नहीं देखा, जयप्रकाश नारायण के आंदोलन को नहीं जाना, न ही मंडल और कमंडल राजनीति के दौर का अनुभव किया है। वे अतीत की स्मृतियों से नहीं, वर्तमान की समस्याओं और भविष्य की अनिश्चितताओं से जूझ रहे हैं। पिछले चार सप्ताह में यह धरना स्थल उनके लिए विचार–विमर्श और आत्ममंथन का मंच बन गया। सोशल मीडिया के जरिए आंदोलन को व्यापक समर्थन मिला। तीन सप्ताह से अधिक समय से अनशन कर रहे पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत को लेकर युवाओं की चिंता भी वैकल्पिक मीडिया मंचों पर साफ दिखाई दी।

मोदी सरकार लंबे समय से यह मानती रही कि विपक्ष की विश्वसनीयता कमजोर है और उसके सामने कोई प्रभावी विकल्प मौजूद नहीं है। यही कारण है कि उसने कॉकरोच जनता पार्टी के उभार को शायद गंभीरता से नहीं लिया। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन, नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ मुस्लिम समुदाय का विरोध, महिला पहलवानों के संघर्ष जैसी कई घटनाओं का सामना सरकार पहले कर चुकी है। इन आंदोलनों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने और उन्हें बदनाम करने की रणनीति भी अपनाई गई। युवाओं के इस उभार को भी शुरुआत में कानून–व्यवस्था का मामला समझा गया। आंदोलन के चरम पर पहुंचने के दौरान दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा की जगह विशेष निदेशक (इंटेलिजेंस) अनुराग कुमार की नियुक्ति की गई। कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियानों का अनुभव रखने वाले अधिकारी द्वारा इस आंदोलन को भी सुरक्षा चुनौती के रूप में देखने में कोई आश्चर्य नहीं है।

यूपीए सरकार के समय निर्भया कांड के बाद भी युवाओं का ऐसा उभार देखने को मिला था, लेकिन तब सोशल मीडिया आज जितना प्रभावशाली नहीं था। आज सोशल मीडिया वैकल्पिक मीडिया का रूप ले चुका है। कभी भाजपा की आईटी सेल ने इसी माध्यम का इस्तेमाल लोगों को संगठित करने और भावनात्मक मुद्दों को उभारने के लिए किया था। लेकिन अब जेन–जी पीढ़ी के हाथों में मौजूद सोशल मीडिया के सामने पुराने प्रचार तंत्र कमजोर पड़ते दिखाई दे रहे हैं। यह घटना बताती है कि कोई भी प्रचार तब तक टिकाऊ नहीं होता जब तक वह जनता की वास्तविक भावनाओं से मेल न खाए।

युवा यह देख रहे हैं कि जिन वादों के साथ मोदी सत्ता में आए थे, वे पीछे छूट गए हैं और भावनात्मक मुद्दे राजनीति के केंद्र में आ गए हैं। रोजगार सृजन में कमी, परीक्षाओं के संचालन में विफलता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी और सत्ता बनाए रखने के लिए राजनीतिक रणनीतियों का अत्यधिक उपयोगकृइन सभी बातों को नई पीढ़ी बारीकी से देख रही है।

हालांकि इसका अर्थ यह नहीं है कि युवा कांग्रेस या अन्य विपक्षी दलों को अपना स्वाभाविक विकल्प मान रहे हैं। पिछले दस वर्षों में विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ व्यापक जन असंतोष खड़ा करने में सफल नहीं रहा। लेकिन जहां विपक्ष असफल रहा, वहां युवाओं ने स्वयं पहल की।

यदि कांग्रेस वास्तव में युवाओं की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती, तो शायद कॉकरोच जनता पार्टी जैसे मंच के उभरने की आवश्यकता ही न पड़ती। दिलचस्प बात यह है कि संसद के मानसून सत्र के पहले दिन सरकार द्वारा पेश किए जाने वाले विधेयकों या विपक्ष द्वारा उठाए जाने वाले मुद्दों से अधिक चर्चा "चलो संसद" अभियान की हुई। इसने न केवल सरकार बल्कि विपक्ष की प्रासंगिकता पर भी सवाल खड़े कर दिए। लंबे समय तक मौन रहने के बाद कांग्रेस नेताओं द्वारा लाठीचार्ज की आलोचना करना और राहुल गांधी का प्रधानमंत्री आवास के सामने धरना देना भी अपनी राजनीतिक उपस्थिति दर्ज कराने का प्रयास माना जा सकता है।

यह समय बताएगा कि क्या इस अनुभव से कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष के रूप में पुनर्जीवित हो पाएगी या नहीं। लोकतंत्र में सरकार के लिए भी एक प्रभावी विपक्ष का होना आवश्यक है। अन्यथा भविष्य में ऐसे और स्वतःस्फूर्त जन आंदोलन उभर सकते हैं।

नैतिक जिम्मेदारी आज की राजनीति में लगभग अप्रचलित शब्द बन चुकी है। एक समय था जब बजट लीक होने पर पूरे मंत्रिमंडल से इस्तीफा लिया जाता था, या रेल और विमान दुर्घटनाओं की जिम्मेदारी लेते हुए मंत्री पद छोड़ देते थे। आज ऐसे उदाहरण दुर्लभ हैं। धर्मेंद्र प्रधान को लगातार चुनावी रणनीतिकार के रूप में इस्तेमाल किया गया। बिहार, हरियाणा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में पार्टी की चुनावी सफलता सुनिश्चित करने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही। ऐसे में वे अपने मंत्रालय पर पूरा ध्यान नहीं दे पाए, यह कहना गलत नहीं होगा। लेकिन यह विफलता केवल उनकी व्यक्तिगत नहीं है। जब राजनीतिक नेतृत्व का मुख्य लक्ष्य चुनावी जीत बन जाता है, तो प्रशासनिक जिम्मेदारियां पीछे छूट जाती हैं। अब सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार हुई गलतियों की जिम्मेदारी स्वीकार कर व्यवस्था पर जनता का भरोसा बहाल करने के लिए ईमानदारी से कदम उठाएगी? यही आने वाले समय की सबसे बड़ी परीक्षा होगी।

जीओ नंबर 3 की बहाली के लिए मुख्यमंत्री चंद्रबाबू सकारात्मक: मंत्री संध्या रानी

(पेन पॉवर न्यूज):
अमरावती, 21 जुलाई: आंध्र प्रदेश की मंत्री गुम्मिडी संध्या रानी ने मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडु के निर्देशों के अनुसार जनजातीय (आदिवासी) समुदायों की समस्याओं के समाधान के लिए 22 जुलाई को बैठक आयोजित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं।

मंत्री ने कहा कि आदिवासियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सामूहिक निर्णय लिया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जीओ नंबर 3 की बहाली के प्रति सकारात्मक रुख रखते हैं। उनके अनुसार, चंद्रबाबू नायडु को 1970 भूमि हस्तांतरण विनियमन अधिनियम सहित सभी जनजातीय मुद्दों की पूरी जानकारी है। संध्या रानी ने कहा कि जीओ नंबर 3 की बहाली के लिए कानूनी विशेषज्ञों और जनजातीय संगठनों के नेताओं के साथ कई दौर की चर्चाएं की गई हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ने सभी आईटीडीए (प्दजमहतंजमक ज्तपइंस क्म. अमसवचउमदज ।हमदबल) क्षेत्रों में जनजातीय प्रतिनिधियों और संगठनों से राय भी एकत्र की है।

मंत्री ने कहा कि गठबंधन सरकार आदिवासियों को 50 वर्ष की आयु से पेंशन, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और आईटीडीए क्षेत्रों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि 1970 अधिनियम आदिवासियों का अधिकार है और केंद्र तथा राज्य सरकारें इसका कड़ाई से पालन कर रही हैं। संध्या रानी ने आरोप लगाया कि

पिछली वाईएसआरसीपी सरकार ने एजेंसी क्षेत्रों में बॉक्साइट खनन की अनुमति दी थी। उन्होंने कहा कि वर्तमान गठबंधन सरकार ने आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए बॉक्साइट खनन की अनुमतियों को रोक दिया है। मंत्री ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडु आदिवासी बच्चों के भविष्य और कल्याण पर लगातार विशेष ध्यान दे रहे हैं। असत्य प्रचार पर विश्वास न करने की अपील करते हुए संध्या रानी ने स्पष्ट किया कि आदिवासियों के साथ मजबूती से खड़े रहने वाली सरकार चंद्रबाबू नायडु के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ही है।

प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए कंट्रोल रूम स्थापित

रामपचोड़वरम, 21 जुलाई: पोलावरम जिला कलेक्टर के. दिनेश कुमार ने बताया कि प्राकृतिक आपदाओं और आपात स्थितियों पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए रामपचोड़वरम आईटीडीए कार्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। भारी बारिश, बाढ़, भूस्खलन, सड़क क्षति, बिजली बाधित होने और अन्य आपात स्थितियों की जानकारी देने के लिए लोग टोल–फ्री नंबर 18004254225 पर संपर्क कर सकते हैं। सूचना मिलते ही संबंधित अधिकारियों के समन्वय से तत्काल कार्रवाई की जाएगी।

ठोस और तरल कचरा प्रबंधन में अधिकारियों की अहम भूमिका : कलेक्टर हरेंद्र प्रसाद

काकीनाडा, 21 जुलाई: जिला कलेक्टर एम.एन. हरेंद्र प्रसाद ने घर–घर कचरा संग्रहण को और मजबूत बनाने तथा ठोस एवं तरल कचरे का वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। ठोस कचरा प्रबंधन नियमदृ 2026 के क्रियान्वयन पर आयोजित कार्यशाला में उन्होंने अधिकारियों से कचरा संग्रहण वाहनों का समयबद्ध कार्यक्रम तैयार कर लोगों को जानकारी देने, गीले और सूखे कचरे को अलग–अलग एकत्र करने तथा आवासीय एवं व्यावसायिक क्षेत्रों से प्रतिदिन कचरा संग्रहण सुनिश्चित करने को कहा। प्रत्येक ग्राम पंचायत में ठोस कचरा प्रबंधन केंद्रों का पूर्ण उपयोग करने और सीवेज को जलाशयों, नहरों एवं गोदावरी नदी में जाने से रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने चेतावनी दी कि खुले में कचरा फेंकने वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

दिव्यांगजनों के साथ हमेशा खड़ी रहेगी सरकार : कलेक्टर दिनेश कुमार

33 लाभार्थियों को सहायक उपकरण और ट्राइसाइकिल वितरित

रामपचोड़वरम, 21 जुलाई: पोलावरम जिला कलेक्टर के. दिनेश कुमार ने कहा कि सरकार दिव्यांगजनों के कल्याण और विकास के लिए हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी। मंगलवार को स्थानीय आईटीडीए परिसर में दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण, कृत्रिम अंग और ट्राइसाइकिल वितरित करने के लिए आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने यह बात कही। कलेक्टर ने बताया कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों और चलने में असमर्थ दिव्यांगजनों सहित 33 लाभार्थियों को कृत्रिम अंग और अन्य सहायक उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं।

रामपचोड़वरम विधायक एवं विधानमंडल समिति की अध्यक्ष मिरियाला शिरीषा देवी ने कहा कि राज्य सरकार दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि दिव्यांग बच्चों की शिक्षा और बौद्धिक विकास के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। पात्र दिव्यांगजनों को दिव्यांगता प्रमाणपत्र जारी कराने के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय किया जाएगा। कार्यक्रम में गणमान्य अतिथियों ने लाभार्थियों को ट्राइसाइकिल, कृत्रिम अंग और अन्य सहायक उपकरण वितरित किए। कार्यक्रम में संयुक्त कलेक्टर सुरपाटी प्रशांत कुमार, राज्य एसटी आयोग की सदस्य गोर्ले सुनीता, आदिवासी कल्याण एवं शिक्षा विभाग के अधिकारी, विद्यार्थी, अभिभावक और अन्य लोग उपस्थित रहे.

माई भारत सेवाओं पर व्यापक जागरूकता जरूरी: जिला कलेक्टर

ओंगोल, 20 जुलाई: प्रकाशम जिला कलेक्टर पी. राजाबाबू ने अधिकारियों को युवाओं में माई भारत सेवाओं के प्रति व्यापक जागरूकता पैदा करने और अधिक से अधिक युवाओं का पंजीकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक में माई भारत के लाभों की जानकारी दी गई। इनमें युवा क्लबों की स्थापना, सामाजिक एवं स्वैच्छिक गतिविधियों में भागीदारी, रोजगार के अवसरों की जानकारी, वित्तीय साक्षरता तथा विशेषज्ञों से संवाद जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। कलेक्टर ने 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को माई भारत मोबाइल ऐप डाउनलोड कर पंजीकरण कराने और सभी विभागों को समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।

बीमारियों की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाएं : कलेक्टर राजाबाबू

लापरवाही बरतने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी

ओंगोल, 21 जुलाई: जिला कलेक्टर पी. राजाबाबू ने चेतावनी दी कि संक्रामक बीमारियों को फैलने से रोकने में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने डायरिया, वायरल बुखार और फूड पॉइजनिंग के मामलों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि हर वर्ष ऐसे मामलों में कमी आनी चाहिए। कल्याण छात्रावासों में रहने वाले बच्चों पर विशेष ध्यान देने तथा भोजन की स्वच्छता, पेयजल की गुणवत्ता और आसपास की साफ–सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने को कहा।

सरकारी सेवाओं और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जनता तक प्रभावी रूप से पहुंचाएं अधिकारी : कलेक्टर

गुंटूर, 21 जुलाई: जिला कलेक्टर सी.एम. साईकांत वर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सरकार द्वारा लागू की जा रही सेवाओं और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जनता तक प्रभावी ढंग से पहुंचाया जाए। कलेक्टर कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में पीजीआरएस, एसआईआर, आंगनवाड़ी सेवाओं, शिक्षा और स्वास्थ्य सहित विभिन्न विषयों की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने आंगनवाड़ी केंद्रों में उपलब्ध सेवाओं के बारे में माताओं में जागरूकता बढ़ाने और मंडल विशेष अधिकारियों को स्कूलों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा आंगनवाड़ी केंद्रों का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए। एसआईआर प्रक्रिया के तहत अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और डुप्लीकेट मतदाताओं के साथ–साथ अनमैप्ड एवं विसंगति वाले मामलों की पूरी जांच कर 24 जुलाई तक प्रक्रिया को पुख्ता तरीके से पूरा करने को कहा। राजनीतिक दलों के साथ बैठकें आयोजित कर आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। उन्होंने वीबीजी रामजी योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने, मॉडल तालाबों के विकास और कर्मचारियों की अंतिम वरिष्ठता सूची जारी करने पर विशेष ध्यान देने को कहा। 'ग्रीन गुंटूर' कार्यक्रम के तहत 15 अगस्त तक 1.25 लाख पौधे लगाने और प्रत्येक पौधे की जियो–टैगिंग करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने 24 जुलाई को होने वाली मेगा पीटीएम के लिए सभी शिक्षण संस्थानों में व्यापक व्यवस्था

करने को कहा। उन्होंने बताया कि 'तल्लिकी वंदनम' योजना के तहत पात्र विद्यार्थियों की माताओं के बैंक खातों में 22 जुलाई को राशि जमा की जाएगी। संयुक्त कलेक्टर आशुतोष श्रीवास्तव ने री–सर्वे, ई–केवाईसी और पीजीआरएस शिकायतों के समाधान में पारदर्शिता बरतने पर जोर दिया।

पारदर्शी और त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार की जाएगी

राजनीतिक दलों का सहयोग आवश्यक : कलेक्टर हरेंद्र प्रसाद

काकीनाडा, 21 जुलाई: जिला कलेक्टर एम.एन. हरेंद्र प्रसाद ने विशेष गहन पुनरीक्षणदृ 2026 (एसआईआर) के तहत पारदर्शी, त्रुटिरहित और निष्पक्ष मतदाता सूची तैयार करने में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से पूर्ण सहयोग देने की अपील की। उन्होंने बताया कि जिले के सभी सात विधानसभा क्षेत्रों में 100 प्रतिशत गणना प्रपत्रों का वितरण पूरा हो चुका है और अब तक 88.05 प्रतिशत प्रपत्रों का डिजिटलीकरण किया गया है। जिले में 1,640 मतदान केंद्रों पर कुल 16,50,811 मतदाता पंजीकृत हैं। 24 जुलाई के बाद मतदान केंद्रों का युक्तिकरण किया जाएगा और लगभग 1,200 मतदाताओं के लिए एक मतदान केंद्र के मानक के अनुसार 184 नए मतदान केंद्रों का प्रस्ताव दिया गया है। प्रारूप मतदाता सूची 31 जुलाई को प्रकाशित की जाएगी, 30 अगस्त तक आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी और अंतिम मतदाता सूची 3 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी।

सिनिंग स्टार विद्यार्थियों को सम्मान

रामपचोड़वरम, 21 जुलाई: पोलावरम जिला कलेक्टर के. दिनेश कुमार ने विद्यार्थियों से लक्ष्य निर्धारित कर कड़ी मेहनत से पढ़ाई करने और अच्छे अंक प्राप्त करने का आह्वान किया। रामपचोड़वरम आईटीडीए बैठक कक्ष में आयोजित कार्यक्रम में कक्षा 10 और इंटरमीडिएट परीक्षाओं में जिला एवं राज्य स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 67 विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। प्रत्येक विद्यार्थी को ₹20,000 की पुरस्कार राशि, पदक और प्रमाणपत्र प्रदान किए गए। विधायक मिरियाला शिरीषा देवी ने विद्यार्थियों से शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने और बाल विवाह से दूर रहने की अपील की। कार्यक्रम में संयुक्त कलेक्टर सुरपाटी प्रशांत कुमार, एसटी आयोग सदस्य गोर्ले सुनीता और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों के लिए बेहतर सेवाओं हेतु कार्ययोजना

आयुष सेवाओं के विस्तार पर डॉ. दासरी चंद्रशेखर के सुझाव

बापटला, 21 जुलाई: ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए बापटला स्थित स्वर्ण भवित (ऑटिज्म प्लस) केंद्र में कार्ययोजना पर चर्चा की गई। आयुष सेल के नोडल अधिकारी एवं सरकारी होम्योपैथिक चिकित्सक डॉ. दासरी चंद्रशेखर ने आयुष पद्धति के माध्यम से उपलब्ध कराई जा सकने वाली चिकित्सा सेवाओं और भविष्य की योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने केंद्र की सेवाओं के बारे में प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से व्यापक जागरूकता फैलाने तथा जिले के सरकारी कार्यालयों में ऑटिज्म जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का सुझाव दिया। जिला कलेक्टर डॉ. वी. विनोद कुमार ने डॉ. चंद्रशेखर के साथ केंद्र के विभिन्न विभागों का निरीक्षण कर उपलब्ध सेवाओं की समीक्षा की।

सूचियों पर आपत्तियां हों तो 22 जुलाई दोपहर से शिकायतें दर्ज

विजयवाड़ा, 21 जुलाई: जिला कलेक्टर डॉ. लक्ष्मीश ने बताया कि राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी 'तल्लिकी वंदनम' योजना के तहत पात्र, अपात्र और जांचाधीन लाभार्थियों की सूचियां 22 जुलाई से जिले के प्रत्येक स्वर्ण ग्राम और स्वर्ण वार्ड कार्यालय में प्रदर्शित की जाएंगी। सूची में नाम नहीं होने, व्यक्तिगत विवरण में त्रुटि, अपात्र सूची में नाम होने या अन्य किसी आपत्ति की स्थिति में संबंधित स्वर्ण ग्रामध्स्वर्ण वार्ड कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। लाभार्थियों से शिकायतें 22 जुलाई दोपहर से स्वीकार की जाएंगी। जिले में वर्तमान में 1,59,812 पात्र माताएं और 2,44,614 बच्चे हैं।

गौरी जी किशन का ग्लैमरस अंदाज़ वायरल

खूबसूरत और प्रतिभाशाली अभिनेत्री गौरी जी किशन इन दिनों मालदीव में छुट्टियां मना रही हैं और अपने स्टाइलिश लुक्स से सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। फ्लोरल ट्यूब को-ऑर्ड सेट में गौरी बेहद आकर्षक नजर आ रही हैं। उनकी यह तस्वीरें फैंस के बीच तेजी से वायरल हो रही हैं और एक क्यूट अभिनेत्री से ग्लैमरस दीवा तक का उनका सफर चर्चा का विषय बना हुआ है।

बिना किसी कट के सेंसर पास हुई 'चेन्नई लव स्टोरी'

किरण अब्बावरम और श्री गौरी प्रिया अभिनीत 'चेन्नई लव स्टोरी' ने सेंसर प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने बिना किसी कट के यू/ए सर्टिफिकेट दिया है। सेंसर बोर्ड ने फिल्म की भावनात्मक कहानी और पारिवारिक मनोरंजन को सराहा। एसकेएन और साई राजेश द्वारा निर्मित यह फिल्म 24 जुलाई को दुनियाभर में रिलीज होगी।

सिर्फ फिल्में करने के लिए फिल्में न करें सीनियर हीरो!

जगपति बाबू और श्रीकांत दशकों से दर्शकों का मनोरंजन करते आ रहे हैं, लेकिन उनकी हालिया एकल रिलीज 'वदला' और 'मिस्टर मिडिल क्लास' बॉक्स ऑफिस पर असफल साबित हुई। दोनों फिल्मों के कथानक दिलचस्प थे, लेकिन कमजोर प्रस्तुति के कारण दर्शकों पर प्रभाव नहीं छोड़ सके। फिल्मी हलकों में चर्चा है कि सीनियर कलाकारों को अब अधिक सोच-समझकर और अपने व्यक्तित्व के अनुरूप भूमिकाएं चुननी चाहिए।

सुनहरी साड़ी में ग्लैमर बिखेरती राद्या ठड़ानी

अभिनेत्री रवीना टंडन की बेटी राद्या ठड़ानी, जो फिल्म 'श्रीनिवास मंगापुरम' से तेलुगु सिनेमा में पदार्पण करने जा रही हैं, अपने नए फोटोशूट से चर्चा में हैं। सुनहरी मेटैलिक साड़ी और मैचिंग ब्लाउज़ में राद्या बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं। उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और उनकी तेलुगु डेब्यू फिल्म को लेकर उत्साह बढ़ा रही हैं।

'आवारापन 2' के लिए रिटायरमेंट से लौटे अरिजीत सिंह?

फिल्म आवारापन 2' के निर्माताओं ने प्रशंसकों को बड़ा सरप्राइज दिया है। लोकप्रिय गायक अरिजीत सिंह ने कथित तौर पर अपनी सेवानिवृत्ति के बाद वापसी करते हुए फिल्म के बहुप्रतीक्षित गीत 'ये आवारापन' को अपनी आवाज दी है। इमरान हाशमी और दिशा पाटनी अभिनीत इस फिल्म को लेकर पहले से ही काफी चर्चा है। अरिजीत की भावनात्मक आवाज और अमाल मलिक के संगीत का यह संगम दर्शकों के बीच भारी उत्साह पैदा कर रहा है।

Printed and Published by **GANTYADA APPARAO** on behalf of **GANTYADA APPARAO**, Printed at Sri Sai Ganga Printers and Publishers Flat No: 504, Bharat Towers, 5th Lane, Dwaraka Nagar, Visakhaptanam, Andhra Pradesh-530016, and Published at H.NO: 38-4-216, MAHARANI STREET, MARRIPALEM, Visakhapatnam, Andhra Pradesh-530018, **Editor: GANTYADA APPARAO.** Mobile : 9059465965, **RNI : APHIN/26/A3657**, editorpenpower@gmail.com